[2013] 1 एस. सी. आर. 243

रविंदर सिंह

बनाम

सुखबीर सिंह एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 67/2013)

11 जनवरी, 2013

[डॉ. बी. एस. चौहान और वी. गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

दंड प्रकिया संहिता, 1973:

धारा 482 – आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना- समान तथ्यों एवं समान अनुतोष हेतु दो आपराधिक रिट आपराधिक रिट याचिकाएं दायर करने के लिए अवमानना याचिका उच्च न्यायालय ने कार्यवाही बंद कर दी- 1989 अधिनियम की धारा 3 (1) (viii) के तहत आपराधिक शिकायत दाखिल करने के लिये दायर की गई उक्त दो आपराधिक याचिकाओं हेतु- अभिनिर्धारित उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका में शामिल मुद्दे को निपटाया गया और मामला स्वयं शिकायतकर्ता के कहने पर बंद किया गया- इसलिए,उस आधार पर नए सिरे से आपराधिक मुकदमा शुरु किये जाने का कोई औचित्य नहीं है न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न्याय प्रशासन के वृहत हित में एवं अन्याय को रोकने के लिये है। इसलिए, यह अदालत पर एक न्यायिक दायित्व है कि न्याय प्रशासन के दौरान किये जा रहे गलत कार्य एवं अनावश्यक न्यायिक प्रकिया की निरंतरता को रोके।

यह भी उतना ही आवश्यक है कि ऐसे आपराधिक अभियोजन के खतरे को नियंत्रित किया जाये। 1989 अधिनियम के तहत दायर शिकायत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (viii) के अतंर्गत प्रस्तुत याचिका खारिज की गई। 3 (1) (viii) आपराधिक कार्यवाही संहिता, 1898 एस। 403(2)

आपराधिक कानूनः

विबंध जारी– व्याख्या - दंड प्रकिया संहिता,1898- धारा 403(2)।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:

धारा 3(1)(viii) - झूठी, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाली या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही दायर करने के लिए अभियोजन - अभिव्यक्ति, झूठी, 'दुर्भावनापूर्ण' और 'परेशान करने वाली' - धारण का अर्थ: केवल इसलिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यह अभियोजन का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, इस कारण से कि अधिनियम के तहत उल्लिखित अपराध इस तथ्य के आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या एक अनुसूचित जनजाति के शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के

उद्देश्य से एक असफल आवेदन का मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था।

अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 1 संख्या द्वारा दायर आईपीसी की धारा 427, 447 और 506 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 254/2005 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। 1.जमानत पर अपनी रिहाई पर, उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को अपने वकील के रूप में नियुक्त किया और अन्य बातों के साथ-साथ एफआईआर संख्या 254/2005 को रद्द करने की मांग करते हुए डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) संख्या 1667/2005 दायर किया। अपीलकर्ता का मामला यह था कि वह बीघा और 4 बिस्वा कृषि भूमि का मालिक व काबिज था, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन कब्ज़ा करने का प्रयास किया और आपराधिक मामला भी दर्ज कराया। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। यद्यपि, एफआईआर संख्या 254 में अंतर्गत धारा 173 और 169 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्टर्स न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी; और राजस्व रिकॉर्ड में कब्जे/कब्जे वाले व्यक्ति के रूप में अपना नाम शामिल करने के प्रतिवादी संख्या 1 के दावे को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 2657/2006 दायर किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर, जिसमें वही कथन किया जो कि पहली रिट याचिका में किया गया था और उसी राहत की मांग की गई थी। उक्त दो रिट याचिका डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी। इसके बाद

प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दो आपराधिक रिट याचिकाएं दायर करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना मामला (सीआरएल) संख्या 10/2007 दायर किया। अपीलकर्ता ने द्वितीय आपराधिक रिट याचिका दायर करने के संबंध में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं.2 ने बिना शर्त माफ़ी मांगी. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के कथन और प्रतिवादी संख्या 2 की माफी को स्वीकार कर लिया और दिनांक 16.02.2009 के आदेश द्वारा आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दो आपराधिक रिट याचिकाएं दायर करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (viii) के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 13.08.2009 द्वारा उक्त शिकायत को खारिज कर दिया। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 का पुनरीक्षण की अनुमति थी. अपीलकर्ता ने याचिका धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आपराधिक शिकायत को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने की मांग करते हुए, उन्होंने अपील दायर की।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया: 1.1 मासूमशा हसनशा मुसलमान के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है,

अभियोजन के लिए यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके तहत उल्लिखित अपराध उसके विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अधिनियम) के तहत इस तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है। [पैरा 9] [258-ई-जी]

मासूमशा हसनशा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2000 (1) एससीआर 1155 = एआईआर 2000 एससी 1876 - पर निर्भर किया गया

1.2 अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (viii) में 'झूठा' शब्द का उपयोग केवल गैरकानूनी झूठ को कवर करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है जी कुछ ऐसा जो बेईमानी, झूठ और धोखाधड़ी है, और कुछ विश्वासघात या धोखाधड़ी करने का इरादा दर्शाता है। न्यायशास्त्र में, 'झूठा' शब्द का उपयोग किसी गलत या आपराधिक कार्य को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जो जानबूझकर और ज्ञानपूर्वक, वास्तविक या रचनात्मक ज्ञान के साथ किया जाता है। असत्य शब्द का प्रयोग व्यापक या संकीर्ण अर्थ में भी किया जा सकता है। [पैरा 11] [259- सी-ई]

बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश बनाम संजीव फैब्रिक्स, 2010 (11) एससीआर 627=(2010) 9 एससीसी 630-पर निर्भर।

1.3 मेलाफ़ाइड, जहां यह आरोप लगाया गया है, उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, वास्तव में साबित करना होगा। यह दूसरों

के अधिकारों की उपेक्षा करने वाला एक जानबूझकर किया गया कार्य है। यह बिना किसी उचित कारण के जानबूझ कर किया गया एक गलत कार्य है। वैध आक्रोश किसी दुर्भावनापूर्ण कृत्य के दायरे में नहीं आता है। लगभग सभी कानूनी जांचों में, मकसद से अलग इरादा ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। आम बोलचाल की भाषा में, किसी दुर्भावनापूर्ण कार्य को बिना उचित कारण या बहाने के जानबूझकर किए गए कार्य के बराबर माना गया है। [पैरा 14 और 16] [260-सी-डी; 261-डी]

कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम गिरजा शंकर पंत एवं अन्य, 2000 (4) पूरक एससीआर 248 = एआईआर 2001 एससी 24 - पर निर्भर।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम दिलीप कुमार रे, 2006 (9) पूरक एससीआर 554 = एआईआर 2007 एससी 976; पंजाब राज्य बनाम वी.के. खन्ना एवं अन्य 2000 (5) सप्ल. एससीआर 200 =एआईआर 2001 एससी 343; आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी, 2003 (2) एससीआर 908-एआईआर 2003 एससी 1941; प्रबोध सागर बनाम पंजाब एसबी एवं अन्य, 2000 (3) एससीआर 866= एआईआर 2000 एससी 1684; और अध्यक्ष और एमडी, बीपीएल लिमिटेड बनाम एस.पी. गुरुराजा और अन्य, 2003 (4) सप्ल। एससीआर 587 = एआईआर 2003 एससी 4536 – संदर्भित

1.4 शब्द "परेशान करने वाला" का अर्थ है 'कानून की प्रक्रिया द्वारा उत्पीड़न', 'उचितीकरण की कमी' या 'परेशान करने के इरादे से'। यह एक ऐसी कार्रवाई का प्रतीक है जिसके पास पर्याप्त आधार नहीं है और जो, इसलिए, केवल प्रतिद्वंद्वी को परेशान करना चाहता है। एक कष्टप्रद कार्यवाही की पहचान यह है कि इसका कानून में कोई आधार नहीं है (या कम से कम कोई स्पष्ट आधार नहीं है); और कार्यवाही का इरादा जो भी हो, इसका एकमात्र प्रभाव दूसरे पक्ष को अधीन करना है असुविधा, उत्पीड़न और व्यय, जो इतना बड़ा है, कि यह दावेदार को मिलने वाले किसी भी संभावित लाभ से असंगत है; और इसमें अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग शामिल है। ऐसी कार्यवाहियाँ उन कार्यवाहियों से भिन्न होती हैं जिनमें न्यायालय की प्रक्रिया का सामान्य और उचित उपयोग शामिल होता है। [पैरा 17] [261-ई-एच]

1.5 इस घटना में कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के उद्देश्य से एक आवेदन दायर किया था, और उसमें असफल रहा था, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। 'साबित नहीं' और 'झूठा' शब्दों के बीच अंतर। केवल इसलिए कि कोई पक्ष किसी तथ्य को साबित करने में असमर्थ है, उसे प्रत्येक मामले में झूठ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। [पैरा 13] [260-ए-बी]

ए. अब्दुल रशीद खान (मृत) और अन्य। वि. पी.ए.के.ए. शाहुल हामिद और अन्य, 2000) 10 एससीसी 636 - पर निर्भर।

2.1 विषय-एस्टोपेल के सिद्धांत को 'कार्रवाई एस्टॉपेल का वादकारण' के रूप में भी जाना जाता है और यह दोहरे खतरे या के सिद्धांत से अलग है; ऑट्रे फ़ॉइस बरी, जैसा कि धारा 403 सीआरपीसी (1898)में सन्निहित है। यह सिद्धांत वहां लागू होता है जहां विवाद के तथ्य पर किसी सक्षम अदालत द्वारा पूर्व अवसर पर सुनवाई की गई हो, और किसी आरोपी के पक्ष में निष्कर्ष निकला हो। यदि वाद का कारण अस्तित्व में निर्धारित किया गया था, यानी, उस पर निर्णय दिया गया था, तो उसे निर्णय में विलय कर दिया गया कहा जाता है। यदि यह निर्धारित किया गया था कि इसका अस्तित्व नहीं है, तो असफल वादी अब यह दावा नहीं कर सकता कि इसका अस्तित्व है; उसे प्रति न्यायिक कार्यवाही से रोक दिया गया है। [पैरा 18] [262-ए-बी-एफ-जी]

मणिपुर प्रशासन, मणिपुर बनाम थोकचोम, बीरा सिंह 1964 (7) एससीआर 123= एआईआर 1965 एससी 87; पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1969 (3) एससीआर 236 = एआईआर 1969 एससी 961; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कोक्किलिगडा मिरैया एवं अन्य, 1969 (2) एससीआर 626=एआईआर 1970 एससी 771;मसूद खान बनाम राज्य यूपी का ए, 1974 (1) एससीआर 793 एआईआर 1974 एससी 28; रविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1975 (3) एससीआर 453 = एआईआर 1975 एससी

856; कन्हिया लाल उमर बनाम आर.के. त्रिवेदी एवं अन्य, 1985 (3) पूरक। एससीआर 1 एआईआर 1986 एससी 111; भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार एवं अन्य, एआईआर 2004 (6) सप्ल। B एस सीआर 1104 2005 एससी 626; और स्वामी आत्मानंद और अन्य बनाम श्री रामकृष्ण तपोवनम और अन्य, 2005 (3) एससीआर 556- एआईआर 2005 एससी 2392; शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2011 (13) एससीआर 247 = (2012) 1 एससीसी 130; प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार 1962 पूरक एससीआर 297 एआईआर 1962 एससी 876; जतिंदर सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर 2001 (1) एससीआर 707 = एआईआर 2001 एससी 784; महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी एवं अन्य, 2002 (4) पूरक। एससीआर 566 एआईआर 2003 एससी 702; पूनम चंद जैन एवं अन्य। वी फजरू 2004 (5) सप्ल। एससीआर 525 एआईआर 2005 एससी 38 - संदर्भित।

2.2 वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर विवादित शिकायत इस आधार पर आधारित है कि दूसरी रिट याचिका दायर करते समय अपीलकर्ता द्वारा झूठी घोषणा की गई है क्योंकि उसने इस सच्चाई को छुपाया था कि उसने पहले भी इसी राहत के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी और ऐसा कानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था और इसलिए, यह एस के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला एक झूठा, कष्टप्रद और दुर्भावनापूर्ण था। अधिनियम की धारा 3(1)(viii). अवमानना

मामले से निपटते समय उच्च न्यायालय ने इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज नहीं किया। पहली रिट याचिका को प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया गया था जबकि दूसरी को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। झूठा हलफनामा दायर करने के मुद्दे को उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में निपटाया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे जोर नहीं दिया। [पैरा 23] [264-जी- एच; 265-ए-बी]

2.3 जहां तक के अवमानना मामले (सीआरएल) संख्या 10/1007 का संबंध है, उच्च न्यायालय का आदेश यह स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता को उसके वकील, अर्थात् प्रतिवादी संख्या द्वारा निर्देशित किया गया था। 2, और आगे यह कि उच्च न्यायालय ने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली थी प्रतिवादी क्रमांक 2, ने उक्त कार्यवाही को छोड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने उपचार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। याचिका निस्तारित कर दी गई, क्योंकि उस पर दबाव नहीं डाला गया। उच्च न्यायालय ने संबंधित मुद्दे से निपटा है और प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर मामला बंद कर दिया गया है। इसलिए, उस आधार पर नए सिरे से आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। [पैरा 6, 8 और 25] [256-एच; 258-सी-ई; 266-बी]

2.4 रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि जिस भूमि पर दोनों पक्ष स्वामित्व/ब्याज का दावा करते हैं, वह शुरू में भारत सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति समुदाय के एक सदस्य को

आवंटित की गई थी, जिसने इसे हस्तांतरित कर दिया था। भूमि आगे चलकर विक्रय की गई और अंततः वर्ष 2005 में अपीलकर्ता को बेच दी गई। प्रतिवादी संख्या 1,जो प्रासंगिक समय में केंद्र सरकार में बहुत उच्च पद पर था, ने दावा किया कि मूल आवंटी द्वारा प्रारंभिक हस्तांतरण अवैध था और आगे चूँकि उक्त भूमि पर उसके पिता द्वारा अतिक्रमण किया गया था, इसलिए उसे राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार था। प्रारंभिक चरण में मूल आवंटी द्वारा स्थानांतरण, भले ही अवैध हो, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार, उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ राजस्व के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेकर डराने-धमकाने की रणनीति अपनाई, बिना यह महसूस किए कि भले ही मूल आवंटी द्वारा प्रारंभिक हस्तांतरण अवैध था, भूमि वापस सरकार को वापस मिल सकती है, न कि केवल इसलिए कि उसके पिता उसी पर अतिक्रमण कर लिया था। [पैरा 24] [265-सी-एफ; जी-एच]

2.5 किसी असाधारण स्थिति से निपटने में न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न्याय प्रशासन के व्यापक हित में है और प्रकट अन्याय को रोकने के लिए है। इस प्रकार, न्याय प्रशासन के दौरान किसी गलती को ठीक करना और अनावश्यक न्यायिक प्रकिया की निरंतरता को रोकना अदालत का न्यायिक दायित्व है। एक न्यायिक प्रक्रिया. जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो सकता है एक साधन के रूप में आपराधिक मुकदमा चलाने का

खतरा अनावश्यक उत्पीड़न का संचालन. किसी व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना से किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी तथ्य-स्थिति में, अदालत को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक्स डेबिटो जस्टिसिया अदालत की अंतर्निहित शक्ति में अंतर्निहित है और पूरा विचार वास्तविक, पूर्ण और पर्याप्त न्याय करना है जिसके लिए अदालतें मौजूद हैं। इस प्रकार, एक स्पष्ट रूप से निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करना अदालत का सर्वोपरि कर्तव्य बन जाता है व्यक्ति पर पूरी तरह से अपोषणीय शिकायत के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णयों को रद्द किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का दिनांक 13.8.2009 का आदेश बहाल किया जाता है। धारा के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दर्ज शिकायत अंतर्गत् धारा 3(1)(viii) अधिनियम को रद्द किया जाता है। [पैरा 25][266-बी-एफ]

चंद्रपाल सिंह एवं अन्य। वी. महाराज सिंह एवं अन्य, एआईआर 1982 एससी 1238- पर भरोसा किया।

श्रीमती. सोमवंती एवं अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। 1963 एससीआर 774-एआईआर 1963 एससी 151; बल्लभदास मथुरादास लखानी और अन्य बनाम नगरपालिका समिति, मलकापुर, एआईआर 1970 एससी 1002; अम्बिका प्रसाद मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। एवं अन्य, एआईआर 1980 एससी 1762; और निपटान निदेशक, ए.पी. एवं अन्य

बनाम एम.आर. अप्पाराव एवं अन्य, 2002 (2) एससीआर 661 एआईआर 2002 एससी एफ1598; डायरेक्ट रिक्रूट क्लास-11 इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 1990 (2) एससीआर 900 एआईआर 1990 एससी 1607; दरियाओ और अन्य। उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1962 एससीआर 574 = एआईआर 1961 एससी 1457; और फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं अन्य बनाम प्रभात मंडल (पंजीकृत), अंधेरी एवं अन्य। 1985 (3) पूरक। एससीआर 766 =एआईआर 1986 एससी 391 जी को संदर्भित करता है।

केस कानून संदर्भ:

2000 (1) एससीआर 1155	पर निर्भर	पैरा 9
2010 (11) एससीआर 627	पर निर्भर	पैरा 12
(2000) 10 एससीसी 636	पर निर्भर	पैरा 13
2000 (4) पूरक एससीआर 248	पर निर्भर	पैरा 14
2006 (9) पूरक एससीआर 554	पैरा 15 का हवाला दिया गया	
2000 (5) पूरक एससीआर 200	पैरा 16 का हवाला दिया गया	
2003 (2) एससीआर 908	पैरा 16 का हवाला दिया गया	
2000 (3) एससीआर 866	पैरा 16 का हवाला दिया गया	

2003 (4) पूरक एससीआर 587 पैरा 16 का हवाला दिया गया

1964 एससीआर 123 पैरा 18 का हवाला दिया गया

1969 (3) एससीआर 236 पैरा 18 का हवाला दिया गया

1969 (2) एससीआर 626 पैरा 18 का हवाला दिया गया

1974 (1) एससीआर 793 पैरा 18 का हवाला दिया गया

1975 (3) एससीआर 453 पैरा 18 का हवाला दिया गया

1985 (3) पूरक। एससीआर 1 पैरा 18 का हवाला दिया गया

2004 (6) सप्ल. एससीआर 1104 पैरा 18 का हवाला दिया गया

2005 (3) एससीआर 556 पैरा 19 का हवाला दिया गया

2011 (13) एससीआर 247 पैरा 19 का हवाला दिया गया

1962 सप्ल. एससीआर 297 पैरा 19 का हवाला दिया गया

2001 (1) एससीआर 707 पैरा 19 का हवाला दिया गया

2002 (4) पूरक एससीआर 566 पैरा 19 का हवाला दिया गया

2004 (5) पूरक एससीआर 525 पर निर्भर पैरा 20

एआईआर 1982 एससी 1238 पैरा 21 का हवाला दिया गया

1963 एससीआर 774	पैरा 21 का हवाला दिया गया
एआईआर 1970 एससी 1002	पैरा 21 का हवाला दिया गया
एआईआर 1980 एससी 1762	पैरा 21 का हवाला दिया गया
2002 (2) एससीआर 661	पैरा 21 का हवाला दिया गया
1990 (2) एससीआर 900	पैरा 22 का हवाला दिया गया
1962 एससीआर 574	पैरा 22 का हवाला दिया गया
1985 (3) पूरक। एससीआर 766	पैरा 22 का हवाला दिया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 67/2013

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सीआर.एम.सी. संख्या 1262/ 2011 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.12.2011 से उत्पन्न।

शेखर नफाडे, शुभांगी तुली, परविंदर चौहान, अपीलकर्ता की ओर से।

राकेश खन्ना, एएसजी, मुकुल शर्मा, प्रसून कुमार, वी.के. सिद्धार्थन, विवेक नारायण शर्मा, राजी जोसेफ, डी.एस. माहरा, बी.वी. बलराम दास, अभिषेक अत्रे, प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

डॉ. बीएस चौहान, **न्यायाधिपति**. 1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सीआरएल.एमसी संख्या 1262/2011 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2011 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा 1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (इसके बाद 'अधिनियम 1989' के रूप में संदर्भित) की धारा 3(1)(viii) के अंतर्गत शुरु G की गई कार्यवाही को रद्द करने हेतु आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियां इस प्रकार हैं:

A. अपीलकर्ता दिल्ली के नंगली पूना गांव की राजस्व संपत्ति में स्थित 1 बीघा और 4 बिस्वा कृषि भूमि का मालिक होने का दावा करता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कथित तौर पर उक्त भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने का प्रयास किया, और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 427, 447 और 506 के तहत 6.4.2005 को 2005 की एफआईआर संख्या 254 भी दर्ज की। इसके बाद इसे ' आईपीसी ' कहा जाएगा)। यद्यपि अपीलकर्ता को उक्त एफआईआर के अनुसरण में गिरफ्तार किया गया था, तथापि, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

बी. व्यथित, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसके मद्देनजर, धारा 447, 323, 429 और 34 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 569/2005 दर्ज की गई। अपीलकर्ता ने प्रदीप राणा, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 को शामिल किया और रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 1667/2005 दायर की, अन्य बातों के साथ-साथ 2005 की एफआईआर संख्या 254 को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की। उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई थी दिनांक 29.9.2005 के आदेश द्वारा सीमा में। इस बीच, अपीलकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में, दिसंबर 2005 में प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

सी. अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर संख्या 254/2005 में लगाए गए आरोपों की जांच करने के बाद, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 और 169 (इसके बाद 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत 20.2.2006 को एक अंतिम रिपोर्टसप्रस्तुत की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों यानी तहसीलदार, नरेला से संपर्क किया और उक्त भूमि के कब्जे वाले व्यक्ति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करने की मांग की। हालाँकि, उनके दावे को तहसीलदार ने दिनांक 22.6.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

डी. इस समय, रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 2657/2006, प्रदीप राणा, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वकील के रूप में 18.11.2006 को अपीलकर्ता के नाम पर दायर की गई थी, जो कि दिए गए कथनों के आधार पर थी। पहली रिट याचिका यानी रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 1667, 2005, और उसमें वही राहत मांगी गई थी। उक्त रिट याचिका दिनांक 17.8.2007 के आदेश द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी। इस बीच, प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में खेती के कब्जे के रूप में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन इसे तहसीलदार, नरेला द्वारा दिनांक 13.8.2007 के आदेश के तहत फिर से खारिज कर दिया गया।

ई. प्रतिवादी संख्या 1 ने 18.9.2007 को अंतर्गत धारा 107/150 सीआरपीसी के तहत एक और शिकायत दर्ज की, और 21.9.2007 को धारा 379, 427 और 34 आईपीसी के तहत 2007 एक नई एफआईआर संख्या 16/2007 दर्ज करवाई, और बाद में धारा 3(1)(v) अधिनियम 1989 के प्रावधान जोडे गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के उद्देश्य से किए गए उसके आवेदन होने पर हुए,तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील दायर की ।

एफ. प्रतिवादी संख्या 1 ने समान राहत की मांग करते हुए दो आपराधिक रिट याचिकाएं दायर करने और इस तथ्य का खुलासा नहीं करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना मामला (सीआरएल) संख्या 10/2007 भी दायर किया था।

पहली रिट के होते हुए दूसरी रिट याचिका दायर की गई, जिसके कारण दिनांक 17.8.2007 के आदेश के तहत उक्त रिट याचिका डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई।

जी. उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता ने दूसरी आपराधिक रिट याचिका दायर करने के संबंध में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए एक जवाब दायर किया, और आगे कहा कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति था, जिसके कारण, उसने प्रदीप को सभी आवश्यक कागजात दिए थे। प्रदीप राणा, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2, और प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 की मिलीभगत से उक्त याचिका दायर की होगी। इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, प्रदीप राणा को नोटिस जारी किया गया, जो पहली याचिका दायर करने और खारिज करने से संबंधित ऐसे तथ्यों का खुलासा किए बिना, दूसरी याचिका दायर करने के लिए उपस्थित हुए और माफी मांगी।

एच. अपीलकर्ता ने 15.12.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 की मिलीभगत से दूसरी रिट याचिका दायर करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के समक्ष शिकायत दर्ज की। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत घटनाओं के संस्करण को स्वीकार कर लिया, और साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दी गई माफी को भी स्वीकार कर लिया और उसके बाद, उसने दिनांक 16.2.2009 के आदेश के तहत

प्रतिवादी संख्या 1 के उदाहरण पर उक्त आपराधिक कार्यवाही को बंद कर दिया।

आई. इसके छह महीने की अवधि के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा झूठी आपराधिक रिट याचिका दायर करने के लिए धारा 3 (1) (viii) अधिनियम 1989 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की,और इससे भी अधिक विशेष रूप से, दूसरी रिट याचिका, उपरोक्त पहली रिट याचिका को दाखिल करने और खारिज करने के तथ्य का खुलासा किए बिना। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिनांक 13.8.2009 के आदेश के तहत उक्त शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही बंद कर दी थी।

जे. उक्त आदेश से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 1 ने एएसजे, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 23/2009 दायर की। एफआईआर संख्या 16/2007 के संबंध में, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) ने प्रतिवादी संख्या 1 के आचरण के साथ-साथ जांच अधिकारी के आचरण के संबंध में गंभीर टिप्पणियां करते हुए अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आदेश दिनांक 13.8.2009 के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को पुनरीक्षण अदालत ने दिनांक 25.10.2010 के आदेश के तहत अनुमति दी

थी, जिसे तब अपीलकर्ता ने धारा के तहत याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। सीआरएल.एमसी संख्या 1262/2011 के रूप में 482 सीआरपीसी, जिसे आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिए, यह अपील।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नफाडे ने प्रस्तुत किया है कि सम्पूर्ण शिकायत मामला दर्ज करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आपराधिक शिकायत को इश्यु एस्टोपेल के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया है, क्योंकि उसी मुद्दे को उच्च न्यायालय ने अपने पहले एक आपराधिक अवमानना मामले में पूरी तरह से निपटाया था, और उच्च न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट था कि गलती, प्रतिवादी संख्या 2, अपीलकर्ता के वकील प्रदीप राणा की थी इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 की माफी भी स्वीकार कर ली और प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर उक्त आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी। चूँकि इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय हो चुका है, और अंततः उच्च न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट अदालत उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ अपील में नहीं बैठ सकती है, आपराधिक अवमानना का उक्त मामला की विषय वस्तु और आरोपों के रूप में बंद किया जा चुका है। उसके समक्ष, शब्दशः हैं और पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। B अधिनियम 1989 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है

कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है, क्योंकि यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि कथित अपराध ऐसी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। . इसके अलावा, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और कष्टप्रद कार्यवाही शब्द को सख्ती से कानूनी अर्थ में समझा जाना चाहिए और इसलिए, ऐसी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का इरादा निश्चित रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। जहां वास्तविक नागरिक मामला न्यायाधीन है, और पक्ष राजस्व अदालतों में अपने विवादों का निपटारा कर रहे हैं, ऐसी कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के आवेदन को खारिज करने में त्रुटि की।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मुकुल शर्मा ने आक्षेपित निर्णय और आदेश का बचाव किया है और प्रस्तुत किया है कि आपराधिक अवमानना के मामले में दर्ज निष्कर्ष प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसी आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोक सकते हैं और वह क्या ये झूठे, दुर्भावनापूर्ण और कष्टप्रद हैं, परीक्षण के दौरान अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। यह वह चरण नहीं है जहां इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। इसके अलावा, जहां तक आपराधिक कार्यवाही का सवाल है, राजस्व अदालत के समक्ष उक्त भूमि के स्वामित्व से संबंधित मुद्दे का लंबित होना कोई बाधा नहीं है। अत: अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है, और दिल्ली राज्य के विद्वान एएसजी श्री राकेश खन्ना और प्रतिवादी संख्या 2 के वकील श्री प्रसून कुमार को सुना है, और रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है।

6. जहां तक अवमानना मामले (सीआरएल) संख्या 10/1007 का सवाल है, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने इस तथ्य से अवगत होने के बाद कि उसके नाम पर दूसरी रिट याचिका दायर की गई थी, बार काउंसिल के समक्ष शिकायत दर्ज की। दिल्ली सरकार ने 29.12.2007 को अपने सचिव के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ (अनुबंध पी/11), जिसमें यह कहा गया था कि 2005 की उक्त दूसरी रिट याचिका संख्या 1667 उनके निर्देशों के बिना, उनके द्वारा हस्ताक्षरित कागजात का उपयोग करके दायर की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय में, उनके कहने पर, सद्भावना। अपीलकर्ता के जवाब पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने 2007 के अवमानना मामले (सीआरएल) संख्या 10 में प्रतिवादी संख्या 2 के वकील प्रदीप राणा को नोटिस जारी किया, और उसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया भले ही दूसरी रिट याचिका अपीलकर्ता के निर्देश पर दायर की गई थी, तथापि, वह अनजाने में, इस तथ्य का उल्लेख करने में विफल रहा कि उसने पहले की रिट याचिका दायर की थी और उसे खारिज कर दिया गया था, जिसके लिए उसने पूर्ण और बिना शर्त माफी मांगी थी।

7. उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.2.2009 के निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अवमानना कार्यवाही का निपटारा कर दिया। आदेश इस प्रकार है:

"रविंदर सिंह के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि सी.आर.एल. रिट याचिका संख्या 1667/05 और सीआरएल। रिट याचिका संख्या 2657/2006 उनके हस्ताक्षरों के तहत दायर की गई थी, लेकिन इसमें कहा गया था कि अंग्रेजी में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं होने के कारण वह याचिका और समर्थन हलफनामों पर हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे और याचिका की सामग्री के संबंध में उनके वकील द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जा रहा था। श्री रविंदर सिंह के विद्वान वकील श्री प्रदीप राणा ने एक के बाद एक दो समान याचिकाएं दायर करने और दूसरी याचिका में यह खुलासा नहीं करने के लिए खेद व्यक्त किया और अयोग्य माफी मांगी कि पहली याचिका दायर की गई थी और खारिज कर दी गई थी।

श्री प्रदीप राणा की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री रविंदर सिंह ने स्वीकार किया है कि दोनों याचिकाएं उनके हस्ताक्षर के तहत दायर की गई थीं और जो कुछ हुआ था उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया था। याचिकाकर्ता वकील के खिलाफ उपचार नहीं अपनाना

चाहता है, तत्काल याचिका का निपटारा नहीं किया जा सकता है। हम याचिका का निपटारा करते हैं क्योंकि इसे दबाया नहीं गया है।" (महत्व जोड़ें)

8. उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि अपीलकर्ता को उसके वकील द्वारा निर्देशित किया गया था और वह स्वयं अंग्रेजी भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था और उसने हिंदी में अपना समर्थन हलफनामा भी दाखिल किया था। इसने प्रतिवादी संख्या 2, प्रदीप राणा द्वारा दी गई अयोग्य माफी को स्वीकार कर लिया था, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वकील कम उम्र का था, भले ही दोनों याचिकाएं अपीलकर्ता के हस्ताक्षर के तहत दायर की गई थीं, उसने इसे छोड़ने का फैसला किया था उक्त कार्यवाही, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपने उपचार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। इसलिए, याचिका का निपटारा कर दिया गया, क्योंकि इसे दबाया नहीं गया था।

9. मासूमशा हसनशा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2000 एससी 1876 में, इस न्यायालय ने अधिनियम 1989 के प्रावधानों के आवेदन पर विचार किया है, और माना है कि केवल इसलिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है। यह अभियोजन के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकता, इस कारण से कि उक्त अधिनियम 1989 के तहत उल्लिखित अपराध इस तथ्य के आधार पर उसके खिलाफ किया जाना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या

अनुसूचित जनजाति का है। ऐसे घटक के अभाव में, अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।

10. अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(viii) इस प्रकार है:

"अत्याचार के अपराधों के लिए सजा:(1) जो कोई, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,-

(i) xx xx xx

viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण या कष्टप्रद मुकदमा या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करना;

ix) xx xx xx

एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।"

11. 'झूठा' शब्द का शब्दकोषीय अर्थ यह है कि, जो सारतः गलत है, या जानबूझकर झूठ, धोखेबाज आदि है। इस प्रकार, 'झूठा' शब्द का उपयोग केवल गैरकानूनी झूठ को कवर करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो बेईमानी, झूठ और धोखाधड़ी है, और कुछ

विश्वासघात या धोखाधड़ी करने का इरादा दर्शाता है। न्यायशास्त्र में, 'झूठा' शब्द का उपयोग किसी गलत या आपराधिक कार्य को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जो जानबूझकर और जानबूझकर, वास्तविक या रचनात्मक ज्ञान के साथ किया जाता है। असत्य शब्द का प्रयोग व्यापक या संकीर्ण अर्थ में भी किया जा सकता है। जब इसके व्यापक अर्थ में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ कुछ ऐसा होता है जो जानबूझकर या जानबूझकर कहा गया हो या नहीं, असत्य है, लेकिन जब इसके संकीर्ण अर्थ में उपयोग किया जाता है, तो यह केवल ऐसे झूठ को कवर कर सकता है, जो जानबूझकर किया गया हो। यह प्रश्न कि किसी विशेष अधिनियम में मिथ्या शब्द का उपयोग प्रतिबंधित अर्थ में किया गया है या व्यापक अर्थ में, यह उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया गया है।

12. कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, उत्तर प्रदेश बनाम संजीव फैब्रिक्स, (2010) 9 एससीसी 630 में, इस न्यायालय ने, कुछ कानूनी शब्दकोशों पर भरोसा करने के बाद, समझाया कि गलत शब्द एक झूठ का वर्णन करता है, जो गलत इरादे या धोखा देने के इरादे से जुड़ा हुआ है। . न्यायालय ने आगे कहा कि आपराधिक अभियोजन के मामले में, जहां परिणाम गंभीर हैं, किसी भी सजा को लागू करने के लिए एक शर्त के रूप में झूठ के मामले में मनःस्थिति के संबंध में तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना चाहिए।

13. इस घटना में कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के उद्देश्य से एक आवेदन दायर किया था, और उसमें असफल रहा था, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। 'साबित नहीं' और 'झूठा' शब्दों के बीच अंतर है। केवल इसलिए B कि कोई पक्ष किसी तथ्य को साबित करने में असमर्थ है, उसे प्रत्येक मामले में झूठ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। (वीडियो: ए. अब्दुल रशीद खान (मृत) और अन्य बनाम पाका शाहुल हामिद और अन्य, (2000) 10 एससीसी 636)।

14. वैध आक्रोश दुर्भावनापूर्ण कृत्य के दायरे में नहीं आता है. लगभग सभी कानूनी जांचों में, मकसद से अलग इरादा ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। आम बोलचाल की भाषा में, किसी दुर्भावनापूर्ण कार्य को बिना उचित कारण या बहाने के जानबूझकर किए गए कार्य के बराबर माना गया है। (वीडियो: कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम गिरजा शंकर पंत एवं अन्य, एआईआर 2001 एससी 24)।

15. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम दिलीप कुमार रे, एआईआर 2007 एससी 976 में, इस न्यायालय ने विभिन्न शब्दकोशों आदि का संदर्भ देकर "दुर्भावनापूर्ण अभियोजन" शब्द के संबंध में अभिनिर्धारित किया –

“कानूनी अर्थ में द्वेष का अर्थ है (1) औचित्य, बहाना या मान्यता प्राप्त शमन के सभी तत्वों की अनुपस्थिति, और (2) या तो (ए) किसी विशेष नुकसान का कारण बनने का वास्तविक इरादा या उसी की हानि की उपस्थिति। सामान्य प्रकृति, या (बी) स्पष्ट और प्रबल संभावना के बारे में जागरूकता के साथ किसी कार्य को जानबूझकर और जानबूझकर करना जिससे ऐसा नुकसान हो सकता है। 'द्वेष' में दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह के लिए जानबूझकर कानून का उल्लंघन शामिल है और निश्चित रूप से नागरिक गलतियों के लिए जिम्मेदारी और अपराध के लिए जिम्मेदारी के संबंध में इसके अलग-अलग अर्थ हैं। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का अर्थ है - संपार्श्विक लाभ प्राप्त करने की इच्छा। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए कार्रवाई के मामले में ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत ये हैं: - दुर्भावना केवल जानबूझकर गलत कार्य करना नहीं है, बल्कि यह स्थापित किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी ने मैलस एनिमस द्वारा कार्रवाई की थी, अर्थात, द्वारा। द्वेष या द्वेष या कोई अप्रत्यक्ष या अनुचित उद्देश्य। लेकिन यदि प्रतिवादी के पास आपराधिक मुकदमा शुरू करने का उचित या संभावित कारण है तो किसी भी प्रकार का द्वेष उसे नुकसान के लिए

उत्तरदायी नहीं बनाएगा। उचित और संभावित कारण ऐसा होना चाहिए जो एक विवेकशील और उचित व्यक्ति के दिमाग पर काम करे; 'द्वेष' और 'उचित और संभावित कारण की चाहत', आपराधिक कार्यवाही शुरू होने की तारीख पर प्रतिवादी के मन की स्थिति का संदर्भ देते हैं और उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर होती है।"

16. मेलाफाईड, जहां यह आरोप लगाया गया है, अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, वास्तव में इसे साबित करना पड़ता है। यह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा करने वाला एक जानबूझकर किया गया कार्य है। यह बिना किसी उचित कारण या बहाने के जानबूझकर किया गया एक गलत कार्य है। (देखें: पंजाब राज्य बनाम वीके खन्ना और अन्य, एआईआर 2001 एससी 343; एपी राज्य और अन्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी, एआईआर 2003 एससी 1941; प्रबोध सागर बनाम पंजाब एसईबी और अन्य, एआईआर 2000 एससी 1684; और अध्यक्ष और एमडी, बीपीएल लिमिटेड बनाम एसपी गुरुराजा और अन्य, एआईआर 2003 एससी 4536)।

17. "परेशान करने वाला" शब्द का अर्थ है 'कानून की प्रक्रिया द्वारा उत्पीड़न', 'उचितता का अभाव' या 'उत्पीड़न करने का इरादा'। यह एक ऐसी कार्रवाई का प्रतीक है जिसके पास पर्याप्त आधार नहीं है, और इसलिए, जो केवल प्रतिद्वंद्वी को परेशान करना चाहता है।

एक कष्टप्रद कार्यवाही की पहचान यह है कि इसका कानून में कोई आधार नहीं है (या कम से कम कोई स्पष्ट आधार नहीं है); और यह कि कार्यवाही का इरादा जो भी हो, इसका एकमात्र प्रभाव दूसरे पक्ष को असुविधा, उत्पीड़न और व्यय के अधीन करना है, जो इतना बड़ा है, कि यह दावेदार को होने वाले किसी भी लाभ के अनुपात से बाहर है; और इसमें अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग शामिल है। ऐसी कार्यवाहियाँ उन कार्यवाहियों से भिन्न होती हैं जिनमें न्यायालय की प्रक्रिया का सामान्य और उचित उपयोग शामिल होता है।

18. मुद्दा-एस्टोपेल के सिद्धांत को एस्टॉपेल का वादकारण के रूप में भी जाना जाता है और यह दोहरे खतरे या के सिद्धांत से अलग है; अन्य सभी को बरी कर दिया जाता है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 403 में सन्निहित है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी तथ्य के मुद्दे पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व अवसर पर सुनवाई की गई हो और किसी अभियुक्त के पक्ष में निष्कर्ष निकाला गया हो। इस तरह के निष्कर्ष से अभियोजन पक्ष के खिलाफ एक रोक या न्यायिक निर्णय का गठन होगा, लेकिन यह एक अलग या विशिष्ट अपराध के लिए आरोपी के मुकदमे और दोषसिद्धि पर रोक के रूप में काम नहीं करेगा। यह केवल उन सबूतों को स्वीकार करने से रोकेगा जो पहले से ही दर्ज किए गए तथ्य की खोज को परेशान करेगा जब आरोपी पर बाद में मुकदमा चलाया जाएगा, यहां तक कि एक अलग अपराध के लिए भी, जिसे सीआरपीसी की धारा 403 (2)

द्वारा अनुमति दी जा सकती है, इस प्रकार, मुद्दे को रोकने का नियम किसी ऐसे मुद्दे पर दोबारा मुकदमा चलाने से रोकता है जो पार्टियों के बीच आपराधिक मुकदमे में तय हो चुका है। यदि किसी लेन-देन से उत्पन्न अपराध के संबंध में एक मुकदमा चला है और आरोपी को बरी कर दिया गया है, तो लेन-देन से उत्पन्न होने वाले कथित अपराध के संबंध में एक और मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए अदालत को असंगत निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। पहले के परीक्षण में पहुंचे निष्कर्ष के साथ, इश्यू एस्टोपेल के नियम द्वारा निषिद्ध है। मुद्दे पर रोक लगाने के नियम को लागू करने के लिए, न केवल दो परीक्षणों में पक्ष समान होने चाहिए, बल्कि मुद्दे में तथ्य, साबित हुआ या नहीं, जैसा कि पहले के परीक्षण में मौजूद था, जो चाहा गया था, उसके समान होना चाहिए। बाद के परीक्षण में पुनः उत्तेजित। यदि कार्रवाई का कारण अस्तित्व में निर्धारित किया गया था, अर्थात, उस पर निर्णय दिया गया था, तो उसे निर्णय में विलय कर दिया गया कहा जाता है। यदि यह निर्धारित किया गया था कि इसका अस्तित्व नहीं है, तो असफल वादी अब यह दावा नहीं कर सकता कि इसका अस्तित्व है; उसे प्रति न्यायिक कार्यवाही से रोक दिया गया है। (देखें: मणिपुर प्रशासन, मणिपुर बनाम थोकचोम, बीरा सिंह, एआईआर 1965 एससी 87; पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1969 एससी 961; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम कोक्किलिगडा मिरैया और अन्य, एआईआर 1970 एससी 771; मसूद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1974

एससी 28; रविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1975 एससी 856; कन्हिया लाल उमर बनाम आरके त्रिवेदी और अन्य, एआईआर 1986 एससी 111; भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार और अन्य, एआईआर 2005 एससी 626; और स्वामी आत्मानंद और अन्य बनाम श्री रामकृष्ण तपोवनम और अन्य, एआईआर 2005 एससी 2392)।

19. शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2012) 1 एससीसी 130 में मौजूदा मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने परमथा नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार एआईआर 1962 एससी 876 में अपने पहले के फैसले पर विचार करने के बाद; जतिंदर सिंह और अन्य। बनाम रंजीत कौर एआईआर 2001 एससी 784; महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी एवं अन्य, एआईआर 2003 एससी 702; पूनम चंद जैन एवं अन्य। वी. फजरू एआईआर 2005 एससी 38 अभिनिर्धारित:

> "यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने पर रोक नहीं लगाता है, बशर्ते कि पिछली शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या शिकायत की प्रकृति या शिकायत की प्रकृति को समझे बिना आदेश पारित किया गया हो। पूरे तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे जा सके या शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद कुछ तथ्य पता चले, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक सकता

था। हालाँकि, दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी, जिसमें पिछली शिकायत का निपटारा शिकायतकर्ता के मामले पर गुण-दोष के आधार पर किया गया हो।"

20. चंद्रपाल सिंह एवं अन्य में। बनाम महाराज सिंह एवं अन्य, एआईआर 1982 एससी 1238, इस अदालत ने माना है कि यह भी उतना ही सच है कि दुखी और निराश वादियों को सस्ते में आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाकर अपनी हताशा को उजागर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ढंग। ऐसी तथ्य-स्थिति में, अदालत को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

21. स्थापित कानूनी प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है, खासकर, जब वह समान पीठ या बड़ी पीठ का हो। यह कहना भी सही है कि भले ही कोई विशेष मुद्दा पहले नहीं उठाया गया हो, या कोई विशेष तर्क दिया गया हो, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया हो, उक्त निर्णय अपना बाध्यकारी प्रभाव नहीं खोता है, बशर्ते कि वह बिंदु जिसके संदर्भ में कोई तर्क बाद में आगे बढ़ाया गया, वास्तव में निर्णय लिया गया है। इसलिए, निर्णय अपना अधिकार नहीं खोएगा, "केवल इसलिए कि इस पर बुरी तरह से तर्क दिया गया, अपर्याप्त रूप से विचार किया गया या गलत तरीके से तर्क दिया गया"। मामले पर विचार किया जाना चाहिए, उसी के अनुपात निर्णय को

ध्यान में रखते हुए, सामान्य कारणों, या सामान्य आधारों पर, जिस पर अदालत का निर्णय आधारित है, या विशेष की विशिष्ट विशिष्टताओं के परीक्षण या सार पर आधारित है। मामला, जो अंततः निर्णय को जन्म देता है। (देखें: श्रीमती सोमवंती और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 1963 एससी 151; बल्लभदास मथुरादास लखानी और अन्य बनाम नगरपालिका समिति, मलकापुर, एआईआर 1970 एससी 1002; अंबिका प्रसाद मिश्रा बनाम यूपी राज्य एवं अन्य, एआईआर 1980 एससी 1762; और निपटान निदेशक, एपी एवं अन्य बनाम एमआर अप्पाराव एवं अन्य, एआईआर 2002 एससी 1598)।

22. सीधी भर्ती क्लास- II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन और बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, एआईआर 1990 एससी 1607, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया है, यह देखते हुए कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति, संक्षेप में नियम का एक हिस्सा है। वह कानून जिसके आधार पर न्याय प्रशासन निर्भर करता है। संविधान द्वारा इस बिंदु पर जोर देना अच्छी तरह से स्थापित है, और एक सक्षम न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर दिए गए फैसले को इसमें शामिल सभी पक्षों को तब तक बाध्य करना चाहिए जब तक कि इसे अपील में रद्द नहीं कर दिया जाता है, और याचिका के रूप में या इसके आधार में बदलाव का प्रयास नहीं किया जाता है। याचिका को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (यह भी

देखें: दरियाओ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 1961 एससी 1457; और फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य बनाम प्रभात मंडल (पंजीकृत), अंधेरी और अन्य । एआईआर 1986 एससी 391)।

23. उपरोक्त तय कानूनी प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए तत्काल मामले का निर्णय लिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर विवाद में शिकायत इस आधार पर आधारित है कि दूसरी रिट याचिका दायर करते समय अपीलकर्ता द्वारा झूठी घोषणा की गई है क्योंकि उसने इस सच्चाई को छुपाया था कि पहले भी इसी राहत के लिए एक रिट याचिका दायर की गई थी और ऐसा कानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया था और इसलिए, यह अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(viii) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाला एक झूठा, कष्टप्रद और दुर्भावनापूर्ण था। अवमानना मामले से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड नहीं किया ऐसी खोज. पहली रिट याचिका को प्रारंभिक रूप से खारिज कर दिया गया था जबकि दूसरी को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। झूठा हलफनामा दायर करने का मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना मामले में निपटाया गया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे जोर नहीं दिया।

24. रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जिस भूमि पर दोनों पक्ष स्वामित्व/हित का दावा करते हैं, वह भूमि शुरू में भारत सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम (गरीबी उन्मूलन) के तहत अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य अनंत राम को आवंटित की गई थी। कार्यक्रम) और उन्होंने इसे

वर्ष 1989 में राम लाल अग्रवाल को बेच दिया, जिन्होंने इसे वर्ष 1990 में अपने बेटे अनिल कुमार अग्रवाल को हस्तांतरित कर दिया। अनिल कुमार अग्रवाल ने इसे वर्ष 2005 में अपीलकर्ता रविंदर सिंह को बेच दिया। प्रतिवादी संख्या 1 जो उस समय केंद्र सरकार में एक उच्च पद पर थे, ने दावा किया कि मूल आवंटी अनंत राम द्वारा राम लाल अग्रवाल के पक्ष में प्रारंभिक हस्तांतरण अवैध था और वह सरकार द्वारा उन्हें आवंटित भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत और इसके अलावा चूंकि उक्त भूमि पर उसके पिता ने अतिक्रमण किया था, इसलिए उसे राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं. 1, स्वयं के लिए कानून बन गया और कानूनी विवाद को तय करने का अधिकार क्षेत्र स्वयं ग्रहण कर लिया, जिसमें वह स्वयं एक श्रेणी के अतिचारी का पुत्र होने के कारण एक पक्ष था। प्रारंभिक चरण में मूल आवंटी द्वारा स्थानांतरण, भले ही अवैध हो, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार, उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ राजस्व के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेकर डराने-धमकाने की रणनीति अपनाई, बिना यह महसूस किए कि भले ही मूल आवंटी अनंत राम द्वारा प्रारंभिक हस्तांतरण अवैध था, भूमि वापस सरकार को वापस मिल सकती है, न कि केवल इसलिए। उसके पिता ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था।

25. उच्च न्यायालय ने इसमें शामिल मुद्दे को निपटाया है और मामला स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर बंद कर दिया गया है। इसलिए, उस आधार पर नए सिरे से आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किसी असाधारण स्थिति से निपटने में न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न्याय प्रशासन के व्यापक हित में है और प्रकट अन्याय को रोकने के लिए है। इस प्रकार, न्याय प्रशासन के दौरान किसी गलती को ठीक करना और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया को जारी रखने से रोकना न्यायालय का न्यायिक दायित्व है। अनावश्यक उत्पीड़न के संचालन के एक साधन के रूप में आपराधिक अभियोजन के खतरे को रोकना बहुत आवश्यक हो सकता है। किसी व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना से किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक्स डेबिटो जस्टिसिया अदालत की अंतर्निहित शक्ति में अंतर्निहित है और पूरा विचार वास्तविक, पूर्ण और पर्याप्त न्याय करना है जिसके लिए अदालतें मौजूद हैं। इस प्रकार, यह अदालत का सर्वोपरि कर्तव्य बन जाता है कि वह एक स्पष्ट रूप से निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करे, न कि पूरी तरह से अपोषणीय शिकायत के आधार पर मुकदमा चलाया जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.2011 के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का दिनांक 13.8.2009 का आदेश बहाल किया जाता है। अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(viii) के प्रावधानों के तहत

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर की गई शिकायत को रद्द कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। मामले को बंद करने से पहले, यह देखना आवश्यक हो सकता है कि यहां की गई कोई भी टिप्पणी उचित प्राधिकारी/अदालत के समक्ष लंबित किसी भी नागरिक/राजस्व मामले में किसी भी पक्ष को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री आरिफ मोहम्मद खान चायल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****